

**PART-I****हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 16 अप्रैल, 2025

**संख्या लैज. 6/2025.**— दि हरियाणा विलेज कॉमन लैन्डज (रेगुलेशन) अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 11 अप्रैल, 2025 की स्वीकृति के अधीन एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4—क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

**2025 का हरियाणा अधिनियम संख्या 5****हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025****हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961****को आगे संशोधित करने के लिए****अधिनियम**

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (iii) में, "कलक्टर द्वारा ऐसे सिद्धांतों के अनुसार तथा ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में यथा निर्धारित ऐसी राशि का पंचायत को भुगतान करने के अध्यक्षीन ऐसे सभी अधिकार, हक तथा हित उक्त पट्टेदार, अंतरिती या उसके विधिक वारिस" शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, "ऐसे सिद्धांतों के अनुसार तथा ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में कलक्टर द्वारा यथा निर्धारित ऐसी राशि का पंचायत को भुगतान करने के अध्यक्षीन ऐसे सभी अधिकार, हक तथा हित उक्त पट्टेदार, अंतरिती या उसके विधिक वारिस" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1961 के पंजाब अधिनियम 18 की धारा 3 का संशोधन।
3. मूल अधिनियम की धारा 5क में,— 1961 के पंजाब अधिनियम 18 की धारा 5क का संशोधन।
  - (i) उप-धारा (1) में, व्याख्या के साथ प्रथम तथा द्वितीय परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा;
  - (ii) उप-धारा (1क) में,—
    - (क) "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "निदेशक, विकास तथा पंचायत विभाग" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
    - (ख) "ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में निर्धारित की जाने वाली ऐसी दर, जो बाजार दर से कम न हो," शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, "ऐसी दर, जो विहित की जाए," शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

रितु गर्ग,  
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,  
विधि तथा विधायी विभाग।